



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2018/माघ 11, 1939

No. 39]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2018/MAGHA 11, 1939

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03)

फा. सं. 15-01/2016-एफएंडईए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) (iv) और (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03) कहा जाएगा।
(2) ये विनियम, आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 के खंड 3 में निम्नलिखित खंड बदला जाएगा:
“3. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार— प्रत्येक सफल पोर्टिंग के लिए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार चार रुपये होगा।”

एस. के. गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./412/17]

टिप्पणी 1 : मूल विनियम दिनांक 20 नवंबर, 2009 के (2009 का 9) की अधिसूचना संख्या 116-5/2009-एमएन के तहत प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन “दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 03)” के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

- 1.1 मौजूदा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता एक सेवा प्रदाता की जगह दूसरे सेवा प्रदाता को अपनाते समय या एक ही सेवा प्रदाता की एक तकनीक की जगह दूसरी तकनीक को अपनाते समय अपने वर्तमान मोबाइल टेलीफोन नंबर को बनाए रख सकते हैं। यह सुविधा उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर को न केवल उसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र (एलएसए) के भीतर बनाए रखने बल्कि पूरे भारत में किसी भी एलएसए में बनाए रखने की अनुमति देती है।

- 1.2 मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी भारत में 2009 से प्रचलन में है, जब दूरसंचार विभाग ने एमएनपी सेवा लाइसेंस दो मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाताओं (इस ज्ञापन में आगे इन्हें एमएनपीएसपी कहा गया है) को जारी किए थे। दूरसंचार विभाग ने एमएनपी सेवा लाइसेंसधारकों के लिए, भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत जारी विनियमों/आदेशों या निदेशों या दूरसंचार विभाग (लाइसेंस प्रदाता) द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का पालन करने को अनिवार्य बनाया है।
- 1.3 दिनांक 20 नवंबर, 2009 के दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम (2009) के अनुसार, भादूविप्रा ने 19 रु. 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' के रूप निर्धारित किए थे, जो प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा एमएनपीएसपी को अदा किए जाने थे। तदनन्तर, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (उनचासवां संशोधन), आदेश, 2009 की अधिसूचना के जरिये उस टैरिफ के उच्चतम प्रभार के रूप में 19 रुपये प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित किए थे जो प्राप्तकर्ता ऑपरेटर ग्राहक से ले सकते थे।
- 1.4 प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का निर्धारण दो एमएनपीएसपी द्वारा 2009 में प्रस्तुत अनुमानित वित्तीय डेटा और अन्य सूचना के आधार पर किया गया था।
- 1.5 2015 तक, एमएनपी सेवा के लिए, पूरा देश दो जोनों में विभाजित था और प्रत्येक जोन में 11 एलएसए थे और केवल एलएसए के भीतर एमएनपी सेवा की अनुमति थी। वित्त वर्ष 2015-16 में उस समय एमएनपी के क्षेत्र का विस्तार किया गया जब 3 जुलाई, 2015 से नेशनल रोलआउट (पूर्ण-एमएनपी) के रूप में पूरे देश में सभी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में एमएनपी सेवा की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और ये 2010-11 के 64 लाख से बढ़कर 2014-15 में 368 लाख हो गयीं। वर्ष 2016-17 में इनकी संख्या बढ़कर 636 लाख तक पहुंच गई। प्राधिकरण ने पिछले दो वर्षों, जब 3 जुलाई, 2015 से पूरे भारत में एमएनपी सेवाएं शुरू की गई थी, के दौरान, पोर्टिंग अनुरोधों में भारी वृद्धि की समीक्षा भी की।
- 1.6 भादूविप्रा ने नवंबर, 2009¹ में 19 रुपये 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' निर्धारित किया था। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, इसका निर्धारण दो एमएनपीएसपी द्वारा 2009 में प्रस्तुत अनुमानित वित्तीय डेटा और अन्य सूचना के आधार पर किया गया था। प्रति पोर्ट प्रभार की गणना 5 वर्षों की अवधि के लिए एमएनपीएसपी की कुल लागत को पोर्टिंग उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या से भाग देकर की गई थी। जहां तक लागत का प्रश्न है तो प्राधिकरण ने दो एमएनपीएसपी की लागत में से जो लागत कम थी, उसी को स्वीकार किया।

विवरण	इकाई	राशि
5 वर्षों के लिए कुल अनुमानित लागत	रु. लाख में	23204.69
5 वर्षों के लिए अनुमानित पोर्टिंग	लाख में	1232.65
5 वर्षों के लिए पोर्टिंग प्रभार प्रति उपभोक्ता	रु. में	18.83
लाइसेंस शुल्क @1%	रु. में	0.19
कुल प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार प्रति उपभोक्ता	रु. में	19.02
पूर्णांक	रु. में	19.00

- 1.7 हालांकि, जब एमएनपीएसपी के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत (पूर्ण आवंटित लागत पद्धति का इस्तेमाल करके) की 2017 में उपरोक्त आंकड़ों से तुलना की गई तो उसमें प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत में भारी गिरावट दिखाई देती है। वर्ष 2016-17 के लिए एमएनपीएसपी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर 'प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार' की गणना निम्नानुसार बनती है :-

विवरण	इकाई	राशि
कुल लागत*	रु. लाख में	1,229.57
प्राप्त पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या	लाख में	310.47
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन लागत	रु. में	3.96
लाइसेंस शुल्क @1%	रु. में	0.04
प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार	रु. में	4.00

¹ 20 नवंबर, 2009 का "दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009"।

- 1.8 उपरोक्त सारणी में दी गई कुल लागत* में एमएनपीएसपी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार, परिचालन लागत (कंसलटेंसी और रॉयल्टी प्रभार समायोजित करने के बाद) और मूल्यहास एवं परिशोधन और नियोजित पूंजी पर 15 प्रतिशत प्रतिफल शामिल है। ऊपर बताई गई लागत और प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार की गणना करते समय प्राधिकरण ने दो एमएनपीएसपी की निम्नतर लागत पर विचार करने के लिए उसी पद्धति और सिद्धांत का उपयोग किया, जिसका पालन प्रारंभिक प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार निर्धारित करने में किया गया था।
- 1.9 दूरसंचार एमएनपी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 के विनियम (2) के अनुसार, प्राधिकरण प्रति पोर्ट प्रभार और डिपिंग प्रभार की समीक्षा और इसमें संशोधन कर सकता है।
- 1.10 दोनों एमएनपीएसपी के वित्तीय लेखों और पिछले दो वर्षों में पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए प्राधिकरण का यह मत है कि ट्रांजेक्शन की अंतर्निहित लागत और संख्या की तुलना में 19 रु. का मौजूदा प्रभार काफी अधिक है। इसलिए प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 18 दिसंबर, 2017 को भादूत्रिपा की वेबसाइट पर ड्राफ्ट “दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017” को अपलोड किया। हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2017 रखी गई थी। जिसे हितधारकों के अनुरोध को मानते हुए, बाद में बढ़ाकर 12 जनवरी, 2018 किया गया था। इस संबंध में 16 जनवरी, 2018 को एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी।
- 1.11 अधिकांश हितधारकों (जिसमें टीएसपी और सीओआई शामिल हैं) ने कहा कि एमएनपी अनुरोधों में वृद्धि और ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही की लागत में कमी को देखते हुए प्रस्तावित 4 रु. प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार भी ज्यादा है और प्राधिकरण को इसे कम करके 2 रु. करने की मांग रखी।
- 1.12 अधिकांश हितधारकों ने कहा कि एमएनपीएसपी द्वारा अपनी मूल कंपनियों को अदा किए गए रॉयल्टी और कंसलटेंसी प्रभार बहुत अधिक हैं हालांकि एमएनपीएसपी ऐसी सेवाएं मुहैया नहीं करा रहे हैं, जिनके लिए रॉयल्टी राशियों का भुगतान किए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण को प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार की गणना करते समय कुल लागत मद के तहत रॉयल्टी पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए दो एमएनपीएसपी की केवल प्रासंगिक लागत पर विचार किया जाना चाहिए।
- 1.13 एक हितधारक का कहना था कि दूरसंचार कंपनी के बंद होने की वजह से मजबूरी वाले पोर्टिंग के मामले में प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार शून्य होना चाहिए। कुछ हितधारकों ने कहा कि एमएनपी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार को पास-थ्रू प्रभार और टीएसपी को पास किए जाने के लिए पिछले वर्षों के दौरान अधिक प्रभार लिए जाने के कारण अधिक वसूली के रूप में माने जाने चाहिए ताकि भावी पोर्टिंग अनुरोध पर बिना किसी लागत के कार्यवाही की जा सके।
- 1.14 दूसरी ओर, एमएनपीएसपी ने कहा कि 19 रु. की मौजूदा प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार उचित है और इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। बाजार के समेकित परिदृश्य को देखते हुए, उपभोक्ताओं को विभिन्न ऑपरेटरों के लिए पोर्ट करने के कम विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या कम हो जाएगी।
- 1.15 ड्राफ्ट “दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017” और ओपन हाउस चर्चा के दौरान हितधारकों से प्राप्त लिखित राय/टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। हितधारकों से प्राप्त राय/टिप्पणियों और अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने यह फैसला किया कि प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार में कमी की जाए क्योंकि एमएनपीएसपी की परिचालन लागतों में काफी कमी आई है और इसी दौरान एमएनपी अनुरोधों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि भी हुई है।
- 1.16 इस संशोधन के परिणामस्वरूप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए उपभोक्ता से वसूले जा सकने वाले प्रभार की उपरी सीमा भी स्वतः उन्नीस रुपये से घट कर चार रुपये मात्र रह जायेगी क्योंकि दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश 2009 की अधिसूचना के अनुसार :-

“प्राप्तकर्ता प्रचालक को उपभोक्ता द्वारा दिया जाने वाला पोर्टिंग प्रभार – दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) के विनियम 3 के तहत, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार ही ग्राहक से लिये जा सकने वाले प्रभार की उपरी सीमा होंगे।”

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2018

TELECOMMUNICATION MOBILE NUMBER PORTABILITY PER PORT TRANSACTION CHARGE AND DIPPING CHARGE (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018 (03 OF 2018)

F. No. 15-01/2016-F&EA.—In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the

following regulations further to amend the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009 (9 of 2009), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2018 (03 of 2018).
(2) They shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.
2. For regulation 3 of the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009, the following regulation shall be substituted, namely: “3. Per Port Transaction charge: - The Per Port Transaction charge for each successful porting shall be rupees four.”

S. K. GUPTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./412/17]

Note 1 : The principal regulations were published vide No. 116-5/2009-MN dated 20th November, 2009 (9 of 2009).

Note 2 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of “The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2018 (03 of 2018)”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

- 1.1 Under the extant Mobile Number Portability (MNP) regime, a subscriber can retain the existing mobile telephone number while switching from one service provider to another or from one technology to another technology of the same service provider. It allows subscribers to retain their mobile number not only within the same Licensed Service Area (LSA) but also Pan India in any LSA.
- 1.2 The Mobile Number Portability is operational in India since 2009, when MNP service licences were issued to two Mobile Number Portability Service Providers (hereinafter referred to as MNPSPs) by the Department of Telecom (DoT). DoT has mandated MNP service licensees to follow the regulations/orders or directions issued by TRAI under TRAI Act, 1997 or any instructions issued by the DoT (licensor) from time to time.
- 1.3 As per Telecommunication Mobile Number portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009 dated 20th November, 2009, TRAI has fixed Rs. 19/- as 'Per Port Transaction Charge' to be paid by the recipient operator to the concerned MNPSP. Further, through notification of the Telecommunication Tariff (Forty-Ninth Amendment) Order, 2009, the Authority prescribed the Per Port Transaction charge of Rs. 19/- as ceiling for the tariff that could be charged from subscriber by the recipient operator.
- 1.4 The Per Port Transaction charge was determined based on the estimated financial data and other information submitted by the two MNPSPs in 2009.
- 1.5 Till 2015, for the purpose of MNP service, the entire country was divided in two zones with 11 LSAs in each zone and MNP service was allowed only within the LSA. The scope of MNP was expanded in the financial year 2015-16, when MNP service was allowed across all licensed service areas on Pan India as the national rollout (Full-MNP) w.e.f. 3rd July 2015. This resulted in huge upsurge in the number of porting requests from 64 lakh in 2010-11 to 368 lakh in 2014-15. This has further gone up to 636 lakh in 2016-17. The Authority also reviewed/ analysed upsurge in the porting requests during the last two years when the MNP services were opened on PAN India basis on 3rd July 2015.
- 1.6 The 'Per Port Transaction Charge' of Rs. 19/- was determined by TRAI in November 2009² based on the estimated financial and other information/ data submitted by the two MNPSPs in 2009 (details given below). The per port transaction charge was computed by dividing the total cost to the MNPSP by the estimated number of porting subscribers, over a period of 5 years. In so far as the cost is concerned, the Authority considered the lower of the cost of the two MNPSPs.

² “The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009” dated 20th November 2009

Particulars	Unit	Amount
Total estimated Cost for 5 years	Rs in Lacs	23204.69
Estimated porting for 5 years	in Lacs	1232.65
Porting Charges per subscriber for 5 years	in Rs	18.83
License fee @1%	in Rs	0.19
Total Per Port Transaction Charges per Subscriber	in Rs	19.02
Rounded off	In Rs.	19.00

- 1.7 However, when the Per Port Transaction cost (using Fully Allocated Cost methodology) based on the audited annual accounts of the MNPSs has been compared in 2017 with the above figures, it shows a significant decline in the per port transaction cost. Based on the audited annual accounts submitted by MNPSs for the year 2016-17, the calculation of 'per port transaction charge works out as follows: -

Particulars	Unit	Amount
Total Cost*	Rs. in Lacs	1,229.57
No. of porting requests received	in Lacs	310.47
Per Port Transaction Cost	in Rs.	3.96
Licence Fee @1%	in Rs.	0.04
Per Port Transaction Charge	in Rs.	4.00

- 1.8 Total cost* in the above table includes the operating expenditure (after adjusting consultancy & royalty charges) and depreciation & amortization and 15% return on capital employed as per the audited annual accounts submitted by MNPSs. While arriving at afore-mentioned cost and the per port transaction charge, the Authority has adopted the same methodology and the principle to consider the lower of the cost of two MNPSs as it was followed at the time of initial fixation of Per Port Transaction Charge.
- 1.9 As per Regulation 6(2) of the Telecommunications MNP per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations 2009, the Authority may review and modify the Per Port Transaction Charge and Dipping Charge.
- 1.10 After reviewing the financial results of both the MNPSs and the upsurge in the volume of porting requests in the past two years, the Authority opined that the present charge of Rs. 19/- is quite high as compared to cost and volumes of transaction involved. The Authority, therefore, placed draft "The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2017" on 18th December, 2017 on TRAI's website for comments of stakeholders. The last date for receiving comments from stakeholders was 29th December, 2017, which was further extended upto 12th January, 2018, considering the requests of stakeholders. An Open House Discussion in this regard was also held on 16th January 2018.
- 1.11 Most of the stakeholders (comprising TSPs and COAI) commented that the proposed per port transaction charge of Rs. 4 are on higher side and should be brought down to Rs. 2.00 by the Authority, considering the surge in the MNP requests and reduction in the cost of serving such requests.
- 1.12 Majority of stakeholders have commented that the royalty and consultancy charges paid by MNPSs to their parent companies are very high. Though the MNPSs are not providing any such service which requires payment of royalty amounts. Thus, the Authority should not consider royalty fee under the item Total Cost while calculating the per port transaction charges. Moreover, only the Relevant Cost of the two MNPSs may be taken into account for the purpose.

- 1.13 One of the stakeholder also commented that per port transaction charge should be nil in case of forced porting due to closure of the telecom company. Few stakeholders commented that MNP per port transaction charge to be allowed as pass through charges and excess recovery due to overcharging during the preceding years to be passed on to TSPs for facilitating the future porting requests without any cost.
- 1.14 On the other hand, MNPSs commented that the current per port transaction charge of Rs.19/- is reasonable and should not be revised downward. Considering the market consolidation scenario, subscribers will be left with fewer choices in the future to port to different operators, which will in turn lead to decline in porting volumes.
- 1.15 The written views/comments received from stakeholders on the draft “The Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge (Amendment) Regulations, 2017” as well as during the open house discussion were analysed. After taking into consideration the views/comments received from stakeholders and the other relevant facts, the Authority has decided that the per port transaction charge may be reduced as the costs of operations of MNPSs have substantially gone down and at the same time the volume of MNP traffic has increased by leaps and bounds.
- 1.16 As a result of this amendment, there will be automatic reduction in ceiling of the charges leviable from subscribers for Mobile Number Portability from Rupees Nineteen to Rupees Four. It will be so because notification of Telecommunication Tariff (Forty-Ninth Amendment) Order, 2009 prescribed the following: -

“Porting charge payable by the subscriber to the Recipient Operator:- The Per Port Transaction charge specified in regulation 3 of the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009(9 of 2009), as ceiling.”